SHIKSHA SAMVAD
International Open Access Peer-Reviewed & Refereed
Journal of Multidisciplinary Research
ISSN: 2584-0983 (Online)
Volume-1, Issue-4, June- 2024
www.shikshasamvad.com

"भारतीय शिक्षा के विशेष परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार"

डॉ निशा द्विवेदी
(शिक्षक शिक्षा विभाग)
असिस्टेंट प्रोफेसर,संबद्ध महाविद्यालय
डॉ राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या

भारत की उच्च शिक्षा परिधि में, पिछले कुछ दशकों में आश्चर्यजनक विस्तार हुआ है। ऐसा यहाँ के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं छात्र और प्राध्यापक समुदाय की संख्या में हुई प्रभूत वृद्धि से प्रमाणित है। 'विश्व बैंक अध्ययन' की एक आख्या से विदित हुआ है कि चीन के बाद भारत विश्व की दूसरी सबसे विशाल शिक्षा व्यवस्था है। इसका सबसे बड़ा अवांछित दुष्परिणाम यह दृष्टिगत हुआ है कि यहाँ की उच्च शिक्षा की गुणता में बड़ी कमी आयी है। साथ ही उसका असम विस्तार हुआ है। इसका सर्वोत्तम प्रमाण यह है कि सेवायोजकों ने इनकी उपाधियों और प्रमाण–पत्रों की मान्यता को संदिग्ध सा करार किया है और वे इनके धारकों की निजी परीक्षाएँ लेने लगे हैं। इससे उपाधियों, नौकरियों से असंबद्ध सी हो चली हैं। इस परिस्थिति में यह विरोधाभास अभिमुख है कि एक ओर हम 'ज्ञानवान समाज' को वरीयता दे रहे हैं, तो दूसरी ओर वही हम इन उपाधियों की प्रामाणिकता को संदेह की नजर से देख रहे हैं। निश्चय ही, इस परिस्थिति की तथ्यभूमि में, हमारी समक्ष 'गुणता संरक्षण और उसके बेहतर प्रबन्धन' की चुनौती आसत्र है। कदाचित, इस कारण से भी देश में विदेशी विश्वविद्यालयों के शैक्षिक अध्ययन केन्द्र स्थापित हो रहे है, और वे हमारी कमजोरी को चुनौती देते, यहाँ भूमण्डलीयकरण और सूचना प्रौद्योगिकी क्रान्ति का आवाहन ही नहीं, उनका अभिप्रवेश कश रहे हैं। इस क्रान्ति परिक्षेत्र में, भारत की प्रतिभागिता, अवश्य ही संतोषप्रद मानी जा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने 21 वीं सदी में शिक्षा के महत्त्व को स्पष्ट करते हुए यह कहा है –

"Higher education is at one and the same time one of the driving forces of economic development, and the local point of learning in a society. It is both reposi tory and creator of knowledge. Moreover, it is the Principal instrument for passing on the accumulated experience, cultural and scientific, of humanity" Delars 1996, P. 130

सच ही है उच्च शिक्षा निश्चय ही आर्थिक विकास साधती है, साथ ही यह किसी भी समाज में अध्ययन का केन्द्रीय स्थान होती है। यह ज्ञान का निधान, साथ ही उसका सर्जक है, यह मानवता के सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक संचित अनुभवों को हस्तान्तरित करने का प्रमुख साधन है। उच्च शिक्षा के 'विश्व घोषणा पत्र– 1998' ने अपने विश्व सम्मेलन में, अक्टूबर, 1998 में, अपनी भूमिका में उत्त्च्च शिक्षा की महत्ता को निम्नवत् स्वीकार किया है–

"On the eve of a new century, there is an unprecedented demand for and a great diversification in higher education, as well as an increased awareness of it vital importance for socioculltural and economic, development, and for building the future for which the younger generations will need to be equipped with new skills, Knowledge and ideals."

"विष्व घोषणा पत्र" ने 21वीं सदी के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए यह सही ही कहां है कि सन्प्रति उच्च शिक्षा के परिक्षेत्र में अवश्य ही बड़े विवधीकरण की आवश्यकता है। इसी के आधार पर राष्ट्री का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास संघ सकेगा। इसके लिए यह वांजनीय होगा कि नगी पीढ़ियों, अभिनव कुशलताओं, ज्ञान और आदशों से संयुजित जो जाएं। इन दिनों उच्च शिक्षा के मापने अनेक नयी ऐसी चुनौतियों सामने हैं जिनका उसके द्वारा समाधान ढूँडा जाना है। नयी प्रौद्योगिकी के दिन प्रतिदिन विकासमान होने के कारण, अब, ज्ञान के उत्पादन, प्रबन्धन, प्रसार–वितरण, पहुँच और उसके नियंत्रण पक्षों का भी पुनसँगठन आवश्यक हो गया है। ऐसी दशा में बिना ऐसा किए राष्ट्रका नारित वांछनीय और बहुपक्षीय विकास नहीं होगा। इधर, समाज, बराबर ज्ञानाधारित होता जा रहा है। इस कारण से उच्च अध्ययन एवं शोध और अधिक आवश्यक हो गया है। हमारे देश और वर्तमान विश्व दोनों में मानवीय मूल्यों के क्षेत्र में संकट आसन है। इस संकट का निवारण भी अपरिहार्य है। यह समाधान उच्च शिक्षा के द्वारा ही साध्य है। एक ओर नयी–नयी समृद्ध पौद्योगिकी के संप्रयोग अनुपयोग द्वारा राष्ट्र का प्रतिस्पर्धा हम बहुमुखी विकास साधना, तो दूसरी ओर हासमान मानव मूल्यों से सम्प्रतिक राष्ट्र–समाज–विश्व की रक्षा कर, दोनों धाराओं के बीच समंजन स्थापित करना। यह नव्य शिक्षा ही करेगी, जो कि एक बड़ी चुनौती है। स्पष्टतः आज के उच्च शिक्षा लोक के द्वारा यह विधेय है कि–

1. उच्च सुयोग्य स्नातक एवं उत्तरदायी नागरिक बनाये जाये, जो मानवीय कार्य व्यापार के सभी देश की आवश्यकताएं पूरी कर सकें, उन्हें यथापेक्षित योग्यताएँ, व्यावसायिक प्रशिक्षणपूर्वक अरपी जाएं, जिनमें उच्चस्तरीय ज्ञान, कुशलतायें अभिनवीकृत पाठ्य वस्तुएँ शामिल हो, और जो कर्तमान और भविष्य के समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं की बराबर पूर्ति कर सकें।
2. उच्च अध्ययन एवं जीवनपर्यन्त अध्ययन के लिए सुविधाएँ प्रदान करना। इस सन्दर्भ में अभिगम कर्ताओं को अधिकाधिक विकल्प नमनियतापूर्वक प्रदान करना जिससे कि उनका वैयलिक विकास हो सके, साथ ही वे नागरिकता का पाठ लोगों को सिखा सकें। ऐसा करते समय विश्वव्यापी दृष्टिकोण रखना होगा।
3. शोध के द्वारा ज्ञान–प्रसार को प्रोत्साहित करना, यह मानकर कि यह समुदाय के प्रति एक सेवा होगी। इससे समुदायों को अपना सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकाम करने में विशेषज्ञ परामर्श मिल सकेगा।

4. आज के सांस्कृतिक वैविध्य के बीच जन–समुदाय में व्यापक दृष्टिकोण का विकास करना।
5. सामाजिक मूल्यों की रक्षा और उनके सम्वर्धन में सहायता प्रदान करना। इससे मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के विकास में भी सहायता होगी।
6. सभी स्तरों की शिक्षा के विकास और उन्नयन में सहयोग प्रदान करना। इस कार्य में प्रशिक्षित अध्यापक विशेष उपयोगी सिद्ध होंगे।

भारत में उच्च शिक्षा तक पहुँच

वर्तमान भारत में उच्च शिक्षा अधिक से अधिक लोगों के लिए सुलभ हो. इसके लिए यह आवश्यक होगा कि विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थाओं का वितरण राज्यों और संघशासित प्रदेशों में एक समान भाव से हो। इस प्रसंग में यह उचित होगा कि भारत में विश्वविद्यालयों के विकास पर एक दृष्टि डाली बाध जिसके लिए यहाँ आगे एक तालिका दी जा रही है––

विश्वविद्यालयों का विकास

दशक	दशक के मध्य खोले गये विश्वविद्यालय	योग	दशक	दशक के मध्य खोले गये विश्वविद्यालय	योग
1	2	3	4	5	6
1857-1866	3	3	1927-1936	2	15
1867-1876	0	3	1937-1946	3	18
1877-1886	0	3	1947-1956	17	35
1887-1896	1	4	1957-1966	33	68
1897-1906	0	4	1967-1976	37	105
1907-1916	2	6	1977-1986	30	135
1917-1926	7	13	1987-2003	82	217

उपर्युक्त तालिका के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 1957 में भारत में मात्र 03 विश्वविद्यालय स्थापित थे। पश्चात् तीन दशकों के अन्तराल में मात्र 01 विश्वविद्यालय बढ़ा। स्वतंत्रता के समय तक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गति अत्यन्त मंद रही। यह संख्या उस समय मात्र 17 रही, जो 56 तक के दशक में बढ़कर 35 हो गयी। पश्चात् विश्वविद्यालयों की स्थापना में पूरे देश में तेजी आयी और वर्ष 2003 तक यह संख्या 217 तक पहुँच गयी। यह संख्या इधर के 03 वर्षों में अर्थात् 2006 तक बढ़कर हो गयी। हैं। इस सन्दर्भ में यह कहना आवश्यक प्रतीत होता है कि इन विश्वविद्यालयों की स्थापना के वितरण में यथेष्ट समता नहीं रही है, जिसकी ओर अब आगे के दशक में दृष्टि डाला जाना हमें आवश्यक प्रतीत होता है।

उच्च्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार के अनेक पहलू हैं। इनमें से कुछ निम्नवत् हैं––

1. उच्च शिक्षा संस्थाओं के मूल्यांकन की गुणवत्ता बढ़ाना

वर्ष 1998 में 'उच्च शिक्षा पर विश्व सम्मेलन' का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन के निमय 11 के द्वारा गुणात्मक मूल्यांकन के बारे में कुछ विचार व्यक्त किये गये हैं। यह बताया गया कि उच्च शिक्षा में गुणता

का प्रश्न बहुआयामी है। इस सन्दर्भ में यह आवश्यक है कि निम्नांकित कई क्षेत्रों में सन्तुलन और वृद्धि को दृष्टिगत रखा जाए–

- शिक्षा एवं अकादमिक कार्यक्रम।
- शोध एवं छात्रवृत्ति ।
- प्राध्यापक मण्डल।
- छात्र समुदाय ।
- भवन ।
- अन्यान्य उपकरण।
- समुदाय के प्रति सेवा आदि।

गुणता के संरक्षण के लिए ज्ञान का विनिमय, अन्तर्क्रिया रूपी कार्यप्रणाली, अध्यापकों और छात्रों की संरचणशीलता, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शोध परियोजनाएँ इन सबकी आयोजना विध्येय है।

इसी भांति प्राध्यापक मण्डल के चुनाव–चयन में, प्राध्यापकों के समय–समय पर किये जाने वाले अभिनवन कार्यक्रमों का आयोजन आदि बातें आवश्य हैं। इसी भांति अधिगम–प्रणाली और शिक्षण–प्रशिक्षण –प्रणाली में नई प्रविधियों का सन्निवेश आवश्यक है। हर्ष की इश्वर केन्द्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 1986 की अपेक्षाओं के अनुपालन स्वरूप "नाक" (NAAC) की स्थापना बंग्लौर में कर दी है।

2. "नाक" (NAAC) की मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सुधार लाना :

इस संस्था में मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार हेतु निम्नांकित बिन्दु स्पष्ट किये गये जिन्हें तालिका रूप में निम्नवत जाना जा सकता है–

मूल्यांकन निष्कर्ष

निकष	विश्वविद्यालय	मूल्यांकन की इकाइयाँ	
		संबद्ध संगठक महाविद्यालय	स्वायत्तशासी महाविद्यालय
पाठ्यक्रमिक पक्ष	15	10	15
शिक्षण–अधिगम एवं मूल्यांकन	25	40	30
शोध, परामर्श एवं विस्तार	15	05	10
पूरक उपकरण एवं अधिगम संसाधन	15	15	15
छात्र सेवायें एवं प्रगति	10	10	10
संगठन एवं प्रबन्धन	10	10	10
स्वास्थ्य सेवाएँ	10	10	10
योग	**100**	**100**	**100**

संस्थानिक गुणांक उपरिअंकित सारे बिन्दुओं के मूल्यांकन स्तर को आधार बना कर दिया जाता है। संस्थाओं के ग्रेड का निर्धारण 09 सूत्रीय मापनी (छपदम च्वपदजंबंसम) के आधार पर किया जाता है। इस मूल्यांकन के स्तर के निर्धारण के लिए "नाक" के इस इस अभियान से संस्थाएँ अपने स्तर को ऊँचा उठाने के लिए हर प्रकार से सक्रिय दिखाई पड़ रही हैं, पर यह प्रक्रिया मुख्यतः वित्तपोषित उच्च शिक्षा संस्थानों पर ही लागू की जा रही है।

3. कक्षा–कक्ष शिक्षण के मूल्यांकन के लिए कुछ बेहतर प्रावधान करना :

कक्षा–कक्ष शिक्षण के सुधार के भी "नाक" (छ।।ब) ने कुछ सुझाव दिये हैं और बताया कि संस्थाओं में निम्नांकित उपकरण बढ़ाये जाएँ, इसका प्रबन्ध किया जाय–

- ओवर हेड प्रोजेक्टर।
- एल. सी. डी प्रोजेक्टर ।

4. सभी संस्थाओं के लिए एक समान मूल्यांकन प्रक्रिया का अपनाया जाना।

5. बिना किसी पूर्व सूचना के संस्थाओं का भौतिक सत्यापन करना।

6. विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के विभागों के मूल्यांकन के लिए कतिपय प्रावधान किया जाना।

7. पाठ्यक्रमानुसार मूल्यांकन के लिए कतिपय प्रावधान किया जाना।

8. नाक (NAAC) की मूल्यांकन–क्रिया के लिए स्वैच्छिक व्यवस्था करना।

9. अध्यापकों के सम्पादन मूल्यांकन के लिए छात्रों के चुनाव में यथेष्ट सावधानी बरतना।

10. शिक्षा में राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने के लिए कतिपय उपाय करना।

11. विश्वविद्यायल अनुदान आयोग की अनुदान–नीति में सुधार लाया जाना, आदि।

उपसंहार :

आशयतः, भारतीय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त गुणात्मक सुधार किये जाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में स्ववित्त पोषित उच्च शिक्षा संस्थाओं की संख्या में आशातीत वृद्धि के कारण, वित्तपोषित संस्थाओं के गुणात्मक सुधार में भी बाधा पड़ रही है। छात्र–राजनीति भी इन दिनों उत्त्च शिक्षा–संस्थाओं में अधिक बढ़ी है। छात्र राजनीतिक दलों के नेताओं का प्रश्रय पा रहे हैं। बाहुबली पेशेवर छात्र–नेता, संस्थाओं की छवि बिगाड़ने में संकोच नहीं करते।' इस भाँति विश्वविद्यालय और उच्च्च शिक्षा संस्थानों में शोध का स्तर गिरता जा रहा है। इसके लिए भी अभियान चलाने की आवश्यकता है। उत्त्च शिक्षा–संस्थाओं के प्रवन्धन में आवश्यकता इस बात की है कि उनका स्वरूप नियोजन, संगठन कार्मिक चयन, प्रोत्साहन योजना एवं नियन्त्रण इन पांच मुख

वाली 'प्रबन्धन प्रक्रिया' से अनुशासित हों। वस्तुतः, उच्च शिक्षा के संस्थान मानव संसाधन विकास के, उनके आदर्श प्रशिक्षण के केन्द्र हैं। अतएव, यह आवश्यक है कि उच्च शिक्षा के सुधार की बात करते समय विश्वविद्यालय प्रशासन, प्रबन्धन के सभी पहलुओं को दृष्टिगत रखा जाए। तभी इन संस्थाओं में गुणता का विकास किया जा सकता है तथा इनमे सभता और जनतांत्रिकता लाई जा सकती है। इन संस्थाओं में गुणता लाने के लिए नियमों और प्रावधानों की पारदर्शी बनाना होगा।"

भारतीय उच्च शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में गुणात्मक सुधार का प्रश्न पूरी गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। इस दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत सरकार का उच्च शिक्षा मंत्रालय, प्रदेशों के उच्च शिक्षा–विभाग, देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, कुलपतियों, निदेशकों, प्राध्यापकों आदि सबका सहयोग लिया जाना चाहिए। आशा की जाती है कि इस दिशा में केन्द्र और राज्य सरकारें कारगर कदम उठायेंगी।

संदर्भ सूची

- एस. एल. शर्मा, रिथिकिंग क्वालिटी..... यूनिवर्सिटी न्यूज़ वॉल्यूम 42, नंबर 3 जनवरी 19 ई. 2004
- Sunil Behari Mohanty : Qualitative Improvement in Higher Education (Part 1) : Univerdity News, 41 (44) P-3
- सुनील बिहारी मोहंतीः उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार खंड 1, यूनिवर्सिटी न्यूज़, 41 (44)
- पुष्पेश पंचः छात्र राजनीति, युवा अपराधी और जनतंत्र, हिंदुस्तान 20 अगस्त 2006
- एल. एल. डेविस एवं फिलिप जी.अल्ट बाच, द डायलेमा आफ हायर एजुकेशन रिफॉर्म यूनिवर्सिटी न्यूज़ नवंबर 25,1996

SHIKSHA SAMVAD
PASSION TOWARDS EXCELLENCE

SHIKSHA SAMVAD

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed or Refereed Research Journal
ISSN: 2584-0983 (Online) Impact-Factor, RPRI-3.87
Volume-01, Issue-04, June- 2024
www.shikshasamvad.com
Certificate Number-June-2024/03

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

डॉ निशा द्विवेदी

For publication of research paper title

"भारतीय शिक्षा के विशेष परिप्रेक्ष्य में उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार"

Published in 'Shiksha Samvad' Peer-Reviewed and Refereed Research Journal and E-ISSN: 2584-0983(Online), Volume-01, Issue-04, Month June, Year- 2024, Impact-Factor, RPRI-3.87.

Dr. Neeraj Yadav
Editor-In-Chief

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Executive-chief- Editor

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.shikshasamvad.com